श्री वारीन्द्र सेठ, उप महानिदेशक एवं राज्य समन्वयक, हरियाणा का आधिकारिक दौरा

(दिनांक: 17.11.2025)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), हरियाणा राज्य के राज्य समन्वयक एवं उप महानिदेशक (डीडीजी) श्री वारीन्द्र सेठ ने 17 नवम्बर 2025 को एनआईसी हरियाणा राज्य केंद्र द्वारा संचालित आईटी पहलों की समीक्षा हेतु एनआईसी हरियाणा का दौरा किया।

एनआईसी हरियाणा के डीडीजी एवं एसआईओ, श्री सरबजीत सिंह ने श्री वारीन्द्र सेठ का हार्दिक एवं उत्साहपूर्ण स्वागत किया। बैठक का शुभारंभ राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी श्री सरबजीत सिंह के स्वागत भाषण के साथ हुआ। इस अवसर पर सभी राज्य स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी जिला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

राज्य समन्वयक ने एनआईसी राज्य केंद्र में पदस्थ सभी एनआईसी अधिकारियों के साथ बातचीत की और एचआरएमएस, सरल, मेडलेपीआर, पीपीपी, ई-ऑफिस आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की । उन्होंने हरियाणा में हुई आईसीटी प्रगति की सराहना की ।

राज्य समन्वयक श्री. सेठ ने सभी अधिकारियों के साथ अपने दृष्टिकोण और अनुभव साझा किये। बैठक के दौरान उन्होंने एनआईसी सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कई सुझाव और मार्गदर्शन दिए ।

बैठक के दौरान, राज्य समन्वयक ने समस्याओं को हल करने, ज्ञान साझा करने और जिला-स्तरीय कार्यों का समर्थन करने के लिए सक्रिय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होंने जिला कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए समस्याओं की समय पर रिपोर्ट करने तथा रचनात्मक सुझाव देने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित किया । चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु राज्य सरकार के विभागों द्वारा गठित किसी भी समिति में भाग लेने से पहले एनआईसी राज्य केंद्र से उचित अनुमोदन की आवश्यकता पर जोर दिया । यह दोहराया गया कि, एनआईसी और भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार, किसी भी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए ।

राज्य समन्वयक ने डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में निरंतर सीखने और नवीनतम तकनीकों और रुझानों के साथ अद्यतन रहने के महत्व पर जोर दिया । अधिकारियों को एनआईसी प्रशिक्षण प्लेटफार्मों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के कार्यक्रमों, ऑनलाइन प्रमाणित पाठ्यक्रमों और सहकर्मी शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से नियमित रूप से अपने कौशल को उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य और उपकरणों, साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं, एआई/एमएल तकनीकों, क्लाउड प्रौद्योगिकियों और परियोजना प्रबंधन पद्धतियों में एनआईसी अधिकारियों की दक्षता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया ।

एनआईसी मुख्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों, परिपत्रों और सलाह का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया गया । उन्होंने अधिकारियों को याद दिलाया कि प्रभावी और अनुपालन कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियमों, आईटी नीतियों, साइबर सुरक्षा सलाह, खरीद मानदंडों, जीआईजीडब्ल्यू अनुपालन, पहुंच मानकों और अन्य सरकारी ढांचे का अद्यतन ज्ञान महत्वपूर्ण है । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे नियमों से अवगत रहना सभी एनआईसी अधिकारियों की प्रमुख जिम्मेदारी है ।

बैठक में एनआईसी से जुड़ी परियोजनाओं में तकनीकी-प्रबंधन नेतृत्व और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने में एनआईसी अधिकारियों की भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित किया गया । अधिकारियों को सभी राज्य और जिला परियोजनाओं में तकनीकी मूल्यांकन, दस्तावेज़ीकरण, सुरक्षा अनुपालन, व्यवहार्यता मूल्यांकन और मानकों का पालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई ।

अपने सम्बोधन में उन्होंने अधिकारियों को बदलते प्रशासनिक और तकनीकी परिवेश को अपनाने का एक अन्य महत्वपूर्ण संदेश दिया । अधिकारियों को पेशेवर विकास और संगठनात्मक दक्षता के हिस्से के रूप में लचीलेपन, सक्रिय समस्या-समाधान और नई प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।

एनआईसी हरियाणा के अधिकारियों ने राज्य समन्वयक को साइबर खतरों को देखते हुए पुराने नेटवर्क बुनियादी ढांचे के उन्नयन की तत्काल आवश्यकता से अवगत कराया । उन्हें कई जिलों में बैंडविड्थ को अपग्रेड करने की आवश्यकता, राज्य और जिला केंद्रों के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद की आवश्यकता के साथ-साथ महत्वपूर्ण नेटवर्क उपकरण के बारे में भी बताया गया ।

बैठक के अंत में, एएमसी प्रबंधन, रखरखाव में देरी, नेटवर्क बुनियादी ढांचे की चुनौतियों और प्रतिस्थापन की आवश्यकता वाले उपकरणों से संबंधित कई मुद्दों के मद्देनजर, एएमसी की स्थिति, बुनियादी ढांचे की कमियों, अनसुलझे तकनीकी मुद्दों और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिशों को कवर करते हुए एक व्यापक, समेकित रिपोर्ट तैयार करने और मुख्यालय में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य समन्वयक के साथ साझा करने का निर्णय लिया गया । उन्हें एनआईसी-मुख्यालय में प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के विभिन्न लंबित प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए के बारे में भी बताया गया ।

बैठक एसआईओ और राज्य समन्वयक की समापन टिप्पणियों के साथ संपन्न हुई, जिन्होंने सभी अधिकारियों की भागीदारी की सराहना की और सामूहिक प्रयास, समय पर कार्रवाई और सर्वोत्तम प्रथाओं के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया । अधिकारियों को प्रभावी और मजबूत ई-गवर्नेंस सेवा वितरण में एनआईसी हरियाणा की भूमिका को मजबूत करने में योगदान जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।

कुछ झलकियाँ :-

समन्वित, संकलित व रिपोर्ट द्वारा :
दीपक सावंत , वैज्ञानिक – एफ
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हरियाणा राज्य, चंडीगढ़

State Visit of Sh. Varindra Seth, Deputy Director General and State Coordinator for Haryana (Dated: 17.11.2025)

Shri Varindra Seth, Deputy Director General (DDG), National Informatics Center being the State coordinator for NIC Haryana State visited Haryana for reviewing the IT Initiatives taken up by NIC Haryana State Center on 17/11/2025.

Shri Varindra Seth was warmly welcomed by Shri Sarbjeet Singh, DDG and SIO, NIC Haryana. The meeting began with a welcome address by Shri Sarbjeet Singh, State Informatics Officer. All State level officials were present during the meeting, and all District Officers joined through video Conference.

State Coordinator interacted with all NIC officers posted at NIC State Centre and discussed various projects like HRMS, SARAL, MedLEaPR, PPP, e-office etc. He appreciated the ICT progress made in Haryana.

State Coordinator Sh. Seth shared his perspectives and experiences with all officials. During the meeting, he provided several suggestions and guidance to enhance the reliability of NIC services.

During the meeting, the State Coordinator highlighted the need for active collaboration to resolve problems, share knowledge, and support district-level work. Officials were encouraged to promptly raise concerns and offer constructive suggestions to strengthen district functioning. Another important point discussed was the need for proper approval from the NIC State Centre before participating in any committees formed by state government officials. It was reiterated that, as per NIC and Government of India protocols, no official should engage in such activities without prior permission from the competent authority.

The State Coordinator emphasized the importance of continuous learning and staying updated with the latest technologies and trends in the field of digital governance. Officials were encouraged to regularly reskill and upgrade their skills through NIC training platforms, Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) programs, online certification courses, and peer learning activities. This was considered essential given the need to maintain the proficiency of NIC officials in the rapidly evolving technological landscape and tools, cybersecurity best practices, AI/ML techniques, cloud technologies, and project management methodologies.

Strict adherence to all guidelines, circulars, and advisories issued by NIC Headquarters, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), and relevant security agencies were emphasized. Officials were reminded that up-to-date knowledge of regulations, IT policies, cybersecurity advisories, procurement norms, GIGW compliance, accessibility standards, and other government frameworks is crucial to ensure effective and compliant functioning. Staying abreast of such regulations was identified as a key responsibility for all NIC officials.

The meeting also focused on the role of NIC officials in ensuring techno-management leadership and quality control in projects involving NIC. Officials were advised to ensure technical evaluation, documentation, security compliance, feasibility assessment, and standards adherence in all state and district projects.

Adapting to changing administrative and technological environments was another key message. Officials were encouraged to demonstrate flexibility, proactive problem-solving, and openness to adapting new systems and processes as part of professional development and organizational efficiency.

NIC Haryana apprised the State Coordinator of the urgent need for upgradation of outdated network infrastructure considering recent cyber threats. He was also informed about the need to upgrade bandwidth in several districts, requirement to procure computer hardware for the state and district centers, as well as critical network equipment.

At the end of the meeting, in light of several issues related to AMC management, maintenance delays, network infrastructure challenges, and equipment requiring replacement, it was decided to prepare a comprehensive, consolidated report covering the status of AMCs, infrastructure deficiencies, unresolved technical issues, and recommendations for corrective action and share with the State Coordinator for further required action at Headquarters. He was also informed about the various pending proposals for trainings and workshops at the NIC-HQ for approval.

The meeting concluded with closing remarks by the SIO and State Coordinator, who commended the participation of all officials and emphasized the need for collective effort, timely action, and adherence to best practices. The officials were encouraged to continue contributing to strengthening NIC Haryana's role in effective and robust e-Governance service delivery.

Few Glimpses :-

Contributed by:-
Sh. Deepak Sawant, Scientist-F,
NIC-Haryana State Centre